

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128]

दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 9, 2014/आश्विन 17, 1936

[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 113

No. 128]

DELHI, THURSDAY, OCTOBER 9, 2014/ASVINA 17, 1936

[N.C.T.D. No. 113

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानीराज्य क्षेत्र दिल्लीसरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2014

फा.सं. आर. 233/ टी.ओ. (एस.)/ टी. सी. फेलिंग/2014-15/5030-37—जबकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र सरकार जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है,

अतः अब दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डॉ अम्बेडकर नेशनल सेंटर की निर्बाध निर्माण के लिए सामाजिक न्याय जनपथ, प्लॉट-ए, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली तक निर्माण हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 1.31 हैक्टेयर (लगभग) क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के उपबंधों से इसके द्वारा छूट प्रदान करती है।

The exemption is subject to fulfillment of the following conditions:

(a) The applicant shall make an advance deposit of an amount of Rs. 38,64,000 (Rupees Thirty Eight Lakh Sixty Four Thousand Only) for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of 5 (five) years as follows:

Project No.	No. of Saplings to be Planted (No. of trees)	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.)	To be Deposited with Forest Division
I	1200	38,64,000	DCF (South)/Tree Officer

- (a) The compensatory plantation will be raised and maintained for 5 (five) years i.e. 745 no. of trees compensatory plantation will be done by the User Agency near construction site and balance 455 no. of trees by the Forest Department at Dera Mandi, Ridge area, New Delhi and to monitor it till its successful establishment.
- (b) The wood obtained on removal of trees shall be handed over by the Ministry of Social Justice & Empowerment, GOI to the officials concerned of MCD for its use on public crematoria in Delhi in consultation with the territorial DCF.
- (c) Before shifting of wood from site of removal of trees, transportation permission for transportation of the said wood shall be obtained from Tree Officer (South).

By Order and in the Name of the

Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

SANJIV KUMAR, Secy.

शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2014

सं.फा. 23(42)/डी.ई./आरटीई/2013-14/1305-1314.—निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 2 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर स्थित समस्त विद्यालयों पर लागू शिक्षा का अधिकार अधिनियम की उक्त धारा में यथापरिभाषित "अलाभित समूह का बालक" के अर्थ के भीतर "उभयलिंग" बच्चे को सन्निविष्ट करने के लिए अधिसूचित करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से और उनके नाम पर,

डॉ. मधु रानी तेवतिया, अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)

#### DIRECTORATE OF EDUCATION

#### NOTIFICATION

Delhi, the 9<sup>th</sup> October, 2014

No. F. DE.23 (42)/DE/RTE/2013-14/1305-1314.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009) (RTE Act) the Lieutenant Governor National Capital Territory of Delhi is pleased to notify inclusion of a "transgender" child within the meaning of "child belonging to disadvantaged group" as defined in the said section of the RTE Act applicable to all schools situated within the National Capital Territory of Delhi.

By Order and in the Name of Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

Dr. MADHU RANI TEOTIA, Addl. Secy. (Education)